



म्यूच्यूअल फंड हेतु सेबी के नए नियम

चर्चा में क्यों?

नवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिये भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India -SEBI) ऐसे सभी म्यूच्यूअल फंड के वरिद्ध कार्यवाही करेगा जिसमें डफिल्ट होने वाली कंपनी के प्रवर्तकों को शेयर के बदले ऋण दिया गया हो। इसके अतिरिक्त SEBI ने म्यूच्यूअल फंड हाउसेस (MF houses) के लिये कुछ नए और सख्त नविश मापदंडों को भी मंजूरी दी है।

मुख्य बंदि

- वशिषजों के अनुसार SEBI द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य उधारकर्त्ताओं के डफिल्ट हो जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम से नवेशकों की रक्षा करना है।
- वर्तमान में म्यूच्यूअल फंड उद्योग एक भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है जिसके लिये उन फंड प्रबंधकों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है जो ऋण योजनाओं के माध्यम से कंपनी प्रवर्तकों को उधार देते हैं।
- 'फंड हाउस' (fund houses) ने कंपनी प्रवर्तकों के साथ ऐसे समझौते किये हैं जिनके अनुसार, 'डफिल्ट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी वे कंपनी के अंशों को किसी एक नश्चिति समय तक बैंच नहीं सकते हैं।'
- परन्तु SEBI ने ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं दी है।
- SEBI के अनुसार म्यूच्यूअल फंड बैंक नहीं होते हैं इसलिये उन्हें ऋण देने के बजाय बाज़ार में नविश करना चाहिये।

कौन होता है प्रमोटर या प्रवर्तक?

- प्रवर्तक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी के प्रवर्तन के बारे में कार्य करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि व्यापार/कंपनी शुरू करने वाले व्यक्ति को ही प्रवर्तक कहते हैं।

नए नविश मापदंड

- म्यूच्यूअल फंड अब केवल सूचीबद्ध ऋण या इक्विटी (Debt or Equity) में ही नविश कर सकते हैं।
- नए मापदंडों के अनुसार अब से जोखिम की गणना परशिोधन (Amortisation) के आधार पर नहीं बल्कि मार्क-टू-मार्केट (mark-to-market) आधार पर की जाएगी।
- किसी भी म्यूच्यूअल फंड को ऋण में नविश करने के लिये चार गुना कवर प्रदान करना होगा और इसे इक्विटी द्वारा भी सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त तरल म्यूच्यूअल फंड योजनाओं (MF Liquid Schemes) को अपनी कुल नविश परसिंपत्तिका 20 प्रतिशत हसिस्सा नकद या गलिट फंड के रूप में बनाए रखना होगा, जो उन्हें प्रतदान/शोधन/मोचन (Redemptions) में मदद कर सकता है।

90

भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड

(Securities and Exchange Board of India)

- भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतभूत और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

■ इसके मुख्य कार्य हैं -

- प्रतभूतियों (securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना ।
- प्रतभूतबाज़ार (securities market) के विकास का उत्तनयन करना तथा उसे वनियमति करना और उससे संबंधति या उसके आनुषंगकि वषियों का प्रावधान करना ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sebi-tightens-norms-for-mfs>

